**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड**
**संयोजक: बैंक ऑफ इण्डिया**

**पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2021-22/426** **दिनांक :09.12.2021**

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र**

महोदय / महोदया,

**विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 77 वीं त्रैमासिक (सितम्बर 2021) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त**

कृपया दिनांक 22.11.2021 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 77 वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है,साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड**

संगलन:- उपरोक्त अनुसार

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड**
**संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया**
**दिनांक: 22.11.2021**
**स्थान- होटल बीएनआर चाणक्य**

## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 77 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत
## Minutes of the 77th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 77वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 22.11.2021 को होटल बीएनआर चाणक्य , राँची के सभागार में आयोजित की गई। बैठक कीं अध्यक्षता एसएलबीसी, झारखंड के संयोजक बैंक **"बैंक ऑफ इंडिया"** के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) श्री अतनु कुमार दास द्वारा की गई।साथ ही बैठक में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक (ईडी) श्री स्वरूप दासगुप्ता, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री संजीव सिन्हा, वित्त विभाग-झारखंड सरकार के प्रधान सचिव, श्री अजय कुमार सिंह, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री अबूबक्कर सिद्दीकी, विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार,श्रीमती दीप्ती जयराज, नाबार्ड, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबन्धक श्री जी. के. नायर, एसएलबीसी, झारखंड के महाप्रबंधक श्री बिक्रम केशरी मिश्र, एसएलबीसी, झारखंड के उप-महाप्रबंधक श्री गणेश टोप्पो एवं श्री सुबोध कुमार उंपस्थित थे। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री जन्मेजय मोहन्ती, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बिनोद कुमार पट्टनायक एवं अन्य सभी बैंकों के प्रतिनिधि तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।

एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक का संचालन श्रीमति प्रियंका द्वारा किया गया। श्रीमति प्रियंका ने बैठक को प्रारम्भ करने हेतु सर्वप्रथम एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री बिक्रम केशरी मिश्र को सभा के संबोधन के लिए आमंत्रित कियागया।

महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री बिक्रम केशरी मिश्र ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, उन्होने बताया कि कोरोना महामारी के कारण काफी लंबे अंतराल के बाद राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रत्यक्ष बैठक के आयोजन पर खुशी जाहीर की। उन्होने सदन को जानकारी दी कि सभी बैंकों द्वारा राज्य की प्रगति में विशेष रूप से वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए कार्य काफी महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। हालाँकि, अभी भी बैंकों

द्वारा कृषि और एमएसएमई अग्रिम के क्षेत्र काफी संभावनाए हैं, जिससे राज्य के ऋण जमा अनुपात मे आवश्यक वृद्धि हो सके।

उन्होने सभी बैंकों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में एसएलबीसी को निरंतर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होने सदन को वर्ष 2021-22 के दौरान सदस्य बैंकों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रदर्शन से अवगत कराया:

- PFRDA द्वारा संचालित APY CITIZEN CHOICE अभियान के तहत एसएलबीसी झारखंड को Award of Par Excellence से नवाजा गया साथ ही LDM पाकुड़ को भी Award of Excellence पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इस अभियान में एसएलबीसी, झारखंड ने मध्यम श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। साथ ही आठ अन्य बैंकों और शेष 23 प्रमुख जिला प्रबंधकों को भी अभियान के दौरान Certificate of Excellence का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। अभियान के तहत राज्य ने आवंटित लक्ष्य का 175% हासिल किया। साथ ही राज्य ने 31 अक्टूबर, 2021 तक APY के वार्षिक लक्ष्य का 75% हासिल किया गया है ।
- NIC / Jan Dhan Darshak वेब पोर्टल के आधार पर वर्ष 2019 में प्रदेश के 811 गांवों को बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित के रूप में चिन्हित किया गया था, जिन्हे सभी बैंकों के सहयोग से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा कवर किया जा चुका है।
- वित्तीय समावेशन की दिशा मे, राज्य में सितंबर तिमाही में बीसी नेटवर्क में 360 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक ने इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान दिया है।
- इस वित्तीय वर्ष से, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, सभी बैंकों द्वारा एसएलबीसी डेटा की रिपोर्टिंग Standardized Automated data flow के आधार पर की जा रही है।
- झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष केसीसी Saturation अभियान के तहत, कृषि विभाग के सहयोग से 5.13 लाख आवेदन सृजित हुए, जिनमें से 1.09 लाख से अधिक आवेदन काफी कम अवधि में बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए । केसीसी आवेदनों की अस्वीकृति के कारणों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 31% आवेदन अधूरे होने के कारण बैंकों द्वारा पुनर्विचार किए जा रहे हैं, 27% आवेदन अनिवार्य स्व-घोषणा पत्र की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न बैंकों मे लंबित हैं, 23% आवेदन एनपीए उधारकर्ता होने के कारण अस्वीकृत किए गए। हालाँकि, यदि पिछले कुछ वर्षों के दौरान केसीसी वित्तपोषण की तुलना की जाए तो यह कहा जा सकता है कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नए स्वीकृत KCC की संख्या 1 लाख से कम रहती थी, लेकिन इस वर्ष केवल 2.5 महीने में इस अभियान के दौरान 1 लाख से अधिक केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो कि काफी सराहनीय है।

- झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक राज्य के कुल 2,16,772 लाभार्थियों को 869 करोड़ रुपये राशि का लाभ दिया गया।
- पीएम स्वानिधि योजना के तहत अब तक बैंकों को अग्रेषित आवेदनों के विरुद्ध 56.71 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 82,561 स्वयं सहायता समूहों को रु. 650.62 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।
- पिछली कई तिमाहियों से ऋण जमा अनुपात मे निरंतर गिरावट के बाद सितंबर तिमाही में ऋण जमा अनुपात मे 2.63% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि 20 ज़िले मे ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, CD Ratio की निगरानी हेतु ज़िले मे उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे विशेष उप-समिति(Special Sub-Committee) का गठन कर Monitorable Action Plan तैयार किया जा रहा है।
- इस तिमाही मे राज्य में "Weaker section" के ऋण प्रवाह (credit flow) कुल ऋण प्रवाह (Total credit flow) का 18.28% दर्ज किया गया है।
- डीएफएस के निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी 24 जिलों में पिछले महीने क्रेडिट आउटरीच अभियान (credit outreach campaigns) के माध्यम से 42,832 लाभार्थियों को 972 करोड़ रुपये के ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए।

इसके अतिरिक्त उन्होने वित्तीय सेवाए विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित अभियानों के ओर सभी बैंकों द्वारा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

- भारत सरकार के पशुपालन और मत्स्य पालन के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए साप्ताहिक जिला स्तरीय विशेष केसीसी अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत सभी जिलों में प्रत्येक शुक्रवार को विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि अभियान की सफलता हेतु अग्रणी ज़िला प्रबन्धक अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।

- पिछली तिमाही से, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान वित्तीय सेवाए विभाग, भारत सरकार द्वारा निरंतर अंतराल पर की जा रही है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना , मुद्रा, स्टैंडअप इंडिया, केसीसी, PMSVANidhi, PMEGP इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा आत्मानिर्भर भारत योजना जैसे AIF, AHIF, PMFME, 2% Interest Subvention Scheme, Special Liquidity Scheme एवं Ethanol Blending Scheme शामिल हैं। उन्होने बताया कि इस संबंध में, बैंकों को सभी योजनाओं के तहत लक्ष्य दिए गए हैं और एसएलबीसी द्वारा समय-समय पर क्रियान्वयन हेतु उचित निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त, डीएफएस, भारत सरकार द्वारा जन सुरक्षा योजनाओं हेतू 2 अक्टूबर, 2021 से Saturation Drive शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा साप्ताहिक प्रदर्शन एसएलबीसी को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे एसएलबीसी द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार को डीएफएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में, भारत सरकार द्वारा एक Special Campaign भी शुरू किया गया है, जिसके अनुसार बैंकों को दिसंबर 2021 तक 18-21 वर्ष के सभी युवाओं को PMJDY खातों से जोड़ना है।

उन्होने आगे जानकारी दी कि झारखंड राज्य की कुल 3215 बैंक-शाखाएँ जिनमे 18,000 से भी कम कर्मचारी कार्यरत हैं, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 20 से अधिक योजनाओं के साथ अपने-अपने बैंकों के व्यवसायिक विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं तथा उन्होने बैंकों द्वारा काफी बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद अच्छे प्रदर्शन की सराहना करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपील की।

अंत में उन्होने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक एसएलबीसी को आने वाले दिनों में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी।

इस सम्बोधन के पश्चात नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डा. जी. के. नायर को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। श्री नायर ने सर्वप्रथम सभी उच्च पदाधिकारियों एवं सहभागियों का अभिवादन किया। तत्पश्चात उन्होने राज्य के ऋण जमा अनुपात पर चिंता जताई जो की निर्धारित बैंचमार्क स्तर (60%) से काफी कम है। उन्होने बताया कि विगत तिमाही में राज्य के CD Ratio में काफी सुधार आया है हालाँकि इसे और सुधारने की आवश्यकता है। उन्होने बैंकों को राज्य के CD Ratio को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कम से कम 50% तक ले जाने का प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रवाह हेतु आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के कुल अग्रिम के सापेक्ष कृषि ऋण कम से कम 18% होना चाहिए, जबकि झारखंड राज्य में केवल 14.46% ही है। उन्होने कहा विगत वर्ष के सितम्बर तिमाही के सापेक्ष में इस वर्ष की सितंबर तिमाही में बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा लेकिन अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। उन्होने राज्य के कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु बैंकों द्वारा अधिक से अधिक कृषि मियादी ऋण (Agriculture Term Loan) दिये जाने की जरूरत पर बल दिया, जिससे राज्य के CD Ratio में वृद्धि हो सके। उन्होने सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुखों से अनुरोध किया कि बैंक शाखाएँ कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा Term Loan उपलब्ध कराने एवं संवितरण करने में तत्परता दिखाएँ।

तत्पश्चात श्री नायर ने KCC Saturation Drive के अंतर्गत हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में सक्रिय KCC ऋण की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है जो कि एक विचारात्मक विषय है। उन्होने सभी बैंकों को अधिक से अधिक किसानों को केसीसी ऋण से जोड़ने का आग्रह किया। साथ ही साथ राज्य के किसानों की फार्म आय किसान उत्पादक

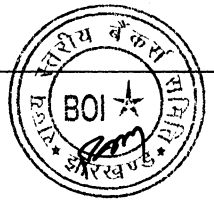

संगठन (Farmer Producer Organisations) के माध्यम से बढ़ाने हेतू अधिक से अधिक FPOs को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होने यह भी बताया कि FPO ऋण की सुरक्षा हेतू ऋण गारंटी योजना भी उपलब्ध है जिसका उपयोग FPO क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को करना चाहिए। अंत में उन्होने सभी बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं के माध्यम से बढ़ाने का अनुरोध किया।

इस सम्बोधन के पश्चात आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा से सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया।

श्री सिन्हा ने सभी उच्च पदाधिकारियों एवं सहभागियों का अभिवादन करते हुये सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आकृष्ट किया।

- Business Correspondents का जिक्र करते हुए श्री सिन्हा ने बताया कि बैंक मित्र बैंकों के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करते हैं अतः जमीनी स्तर पर ग्राहकों को BC द्वारा प्रदान की गई सेवा में कोई भी कमी बैंक की प्रतिष्ठा में जोखिम पैदा करती है । श्री सिन्हा ने एईपीएस (AePS) अनियमितताओं के लिए बैंकों के बीसी आउटलेट्स पर किए जा रहे लेनदेन की निगरानी के लिए एक परिभाषित ढांचे की आवश्यकता बतायी। जिससे बीसी के माध्यम से किए जा रहे लेनदेन की मात्रा का आकलन किया जाए, एवं यह पता लगाया जा सके कि कोई लेनदेन दोहराया तो नहीं जा रहा है साथ ही सीएसपी पर ग्राहक द्वारा किए गए वास्तविक लेनदेन की पावती (Receipt) उत्पन्न की जा रही है या नहीं। तकनीकी कारणों से बीसी के कामकाज को प्रभावित होने के रोकथाम हेतु उचित कनेक्टिविटी की आवश्यकता बतायी । उन्होने एसएलबीसी को सलाह दी कि इस विषय से संबन्धित उप-समिति मे इस संबंध में प्रत्येक बैंक द्वारा framework operationalized की जांच करे और SLBC बैंकों के monitoring mechanism को आगामी बैठक में शामिल करे।
- हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र COVID19 महामारी के कारण तनावग्रस्त है और ऐसे उत्पादों की मांग में हुये इजाफे हुए संस्थागत ऋण सहायता की आवश्यकता है । बैंक इस क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर संबन्धित उप-समिति में चर्चा करते हुये अगली एसएलबीसी बैठक में प्रस्तुत करने की बात की।
- एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स में सिफारिश के अनुसार एमएसएमई के वित्तपोषण में अपेक्षा के अनुरूप राज्य में बैंकों का प्रदर्शन काफी नीचे रहा है । इस क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता बतायी। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा CGMSE कवरेज और उद्योग आधार पंजीकरण के अभाव में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के वर्गीकरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता का ज़िक्र किया । श्री सिन्हा ने बताया कि संबंधित उप-समिति बैंकों के उपरोक्त मुद्दों और चिंताओं पर विचार-विमर्श कर सकती है और इस वर्ग को ऋण देने में प्राप्त सुझावों को आगामी एसएलबीसी की बैठक मे रखा जा सकता है।
- झारखंड राज्य के 24 में से 16 जिलों के पिछले आधे दशक के दौरान लगातार 40 प्रतिशत से कम सीडी अनुपात की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई रांची इसके कारणों का आकलन हेतु जिलों में जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया है। निष्कर्षों के अवलोकन से पता चलता है कि भूमि रिकॉर्ड के अद्यतन की कमी, बैंकों

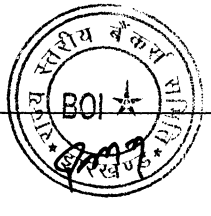

के ग्राहकों द्वारा व्यावसायिक रिकॉर्ड बनाए रखने में असमर्थता, आईटीआर/जीएसटी दाखिल करते समय अंडर-रिपोर्टिंग तथा राज्य में माइग्रेशन, राज्य के कम सीडी अनुपात के कुछ प्रमुख कारण हैं। विस्तृत निष्कर्ष शीघ्र ही एसएलबीसी के संयोजक के साथ साझा किए जाएंगे ताकि उप-समिति इन निष्कर्षों पर विचार-विमर्श करके प्रत्येक जिले के हितधारकों के साथ सीडी अनुपात को बढ़ाने में संबंधित भूमिका निभाने का आग्रह करे। उप-समिति के विचार-विमर्श का परिणाम अगली बैठक में एसएलबीसी को दिया जा सकता है।

- RSETI प्रशिक्षुओं के संबंध मे, बताया क्रेडिट लिंकेज के लिए TAT 6 महीने के भीतर 15% था और 6 महीने या उससे अधिक के लिए 9% था। TAT को कम करने के लिए, एसएलबीसी, संयोजक द्वारा विभिन्न बैंकों में आवेदनों की प्रगति पर नज़र रखने हेतु एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने की आवश्यकता बतायी जिससे प्रगति की जानकारी आगामी एसएलबीसी की बैठक में दी जा सके।
- श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य ने स्टार्ट-अप संबंधित मापदंडों पर काफी अच्छा काम किया जैसे- Policy implementation, Angel and Venture Funding, Simplified Regulation, Awareness and Outreach. संबंधित विभाग इन विषयों हेतु एक पोर्टल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे स्टार्ट-अप और वेंचर कैपिटलिस्ट को एक साथ लाकर त्वरित कार्रवाई हेतु एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध हो सके। जिससे प्राप्त इनपुट से राज्य में Start-Up के लिए उचित नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
- आरबीआई ने 18 नवंबर, 2021 को अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्स के जरिए कर्ज देने सहित डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी की है जिसके लिए सभी स्टेक होल्डेर्स से सुझाव मांगा गया है। उन्होने एसएलबीसी संयोजक बैंक से राज्य सरकार तथा सभी संबन्धित हितधारकों से परामर्श के बाद आरबीआई को अपनी टिप्पणियां 31 दिसम्बर,2021 तक प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

इस सम्बोधन के पश्चात सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार से श्री अबूबक्कर सिद्दीकी को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। श्री अबूबक्कर सिद्दीकी ने सितम्बर तिमाही की उपलब्धियों के संबंध में सभा को बताया कि कुछ क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है, किन्तु कृषि क्षेत्र में बैंकों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होने सभा को जानकारी दी कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "विश्व आदिवासी दिवस" के दिन राज्य के किसानों को बिरसा किसान का दर्जा दिया गया तथा राज्य के सभी बिरसा किसानों को केसीसी सुविधा देने की बात कही थी, चाहे वो पीएम किसान के लाभूक हो या नहीं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला प्रशासन को केसीसी आवेदन सृजित करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया है। राज्य की स्थापना हुये 21 वर्ष हो चुके हैं, किन्तु केसीसी में प्रगति की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य में सितम्बर, 2021 की रिपोर्टिंग के अनुसार बैंकों द्वारा लगभग 13 लाख केसीसी जारी किया गया है, जबकि राज्य में कुल 30 लाख पंजीकृत पीएम किसान लाभूक हैं एवं कुल किसानों की संख्या लगभग 50 लाख है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि कम-से-कम पीएम किसान लाभूकों को केसीसी अवश्य उपलब्ध कराया जाए। उन्होने कहा कि पिछले एक वर्ष से इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, किन्तु प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होने मुख्यमंत्री महोदय के कुछ दिन पहले दुमका दौरे का जिक्र करते हुये बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा के दौरान केसीसी

की अभी तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होने बैंकों में केसीसी आवेदनों के High Pendency पर चिंता व्यक्त की तथा बैंकों को इसपर स्वत: सज्ञान लेने हेतु अनुरोध किया।

उन्होने इसी संदर्भ में आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा 8.48 लाख आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमे केवल 2.79 आवेदन ही बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। उन्होने सीजीएम नाबार्ड के कथन से सहमति जताते हुये कहा कि राज्य सरकार द्वारा केसीसी की रिपोर्टिंग एवं बैंक द्वारा दी गई रिपोर्टिंग में काफी अंतर है। इसके लिए उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है कि वे बैंक शाखाओं को आवेदन देते समय पावती अवश्य लें। साथ ही साथ उन्होने बैंक के राज्य स्तरीय प्रमुखों से भी अनुरोध किया कि वे अपने शाखाओं को आवेदन प्राप्ति की पावती रशीद अवश्य देने को निर्देशित करे। उन्होने बताया कि प्रत्येक केसीसी आवेदन को सृजित करने में जिला कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों की मेहनत होती है एवं बैंक शाखा द्वारा आवेदन नहीं प्राप्त होने की सूचना देना सही नहीं है। उन्होने बैंक शाखाओं एवं जिला प्रशासन दोनों को इसकी जाँच करने की सलाह दी। उन्होने इसके नीरकरन हेतु पोर्टल तैयार करने की आवश्यकता बताई। केसीसी आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है, तो उसे जिला कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ठीक करवाने हेतु विशेष बीएलबीसी बैठक आयोजित कर उसमें चर्चा करें। इसी प्रकार, उन्होने डेयरी एवं फिशेरी किसानों को केसीसी जारी करने के आकड़े देखकर कहा कि बैंकों द्वारा आवेदन स्वीकृति की तुलना में Reject किए जाने वाले आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होने डेयरी के अंतर्गत झारख़ंड मिल्क फ़ैडरेशन से जुड़े किसानों के केसीसी आवेदनों के रिजेक्ट किए जाने पर चिंता जताते हुये कहा कि ये किसान जेएमएफ़ को दुग्ध की आपूर्ति करते हैं और जेएमएफ़ द्वारा दुग्ध का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।इस प्रकार के खातो मे बैंकों को रिकवरी मे कम परेशानी होगी अतः इन आवेदनों के निष्पादन हेतु बैंको को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होने बैंक प्रमुखों से अनुरोध किया कि केवल एक अधिकारी या कम स्टाफ वाले शाखाओं में लंबित आवेदनों को Centralized Mechanism द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

उन्होने झारखंड कृषि ऋण माफी के संदर्भ में कहा कि ऋण माफी हेतु बैंकों द्वारा कुल 9.06 लाख eligible खातों में केवल 5.80 केसीसी खातों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि इस योजना हेतु सरकार के पास 1,500 करोड़ की राशि उपलब्ध है एवं जिस बैंक का डाटा जल्दी अपलोड होगा उसे पहले लाभ मिलेगा।

इसी क्रम में, उन्होने एग्री इन्फ्रा फ़ंड की उपलब्धि की चर्चा करते हुये कहा कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में झारखंड राज्य की उपलब्धि नगण्य है, जबकि राज्य का लक्ष्य काफी अधिक है इस संदर्भ में उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक जिले एग्री इन्फ्रा फ़ंड योजना के अंतर्गत कम से कम एक ऋण स्वीकृति करें। उन्होने बैंकों से इस योजना में अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने एवं स्वीकृत करने को कहा। उन्होने बैंकों से FPOs एवं Horticulture में फ़ाइनेंस करने के लिए विशेष अनुरोध किया। साथ ही साथ उन्होने बैंकों को सरकारी योजनाओं के फ़ाइनेंस में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया, जिससे राज्य का सीडी ratio में सुधार आयेगा तथा राज्य के गरीबों को भी मदद मिलेगी। अंत में, उन्होने सभा को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न

योजनाओं की जानकारी देते हुये बताया कि विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा 40% से 90% तक अनुदान दिया जाता है,अतः बैंको को आगे आकर शेष राशि को बैंक द्वारा फ़ाइनेंस किया जा सकता है।

इस सम्बोधन के पश्चात झारखंड सरकार के योजना-सह-वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। श्री सिंह ने सभा को संबोधित करते हुये बताया कि एसएलबीसी द्वारा राज्य में बैंकों को दिये गए एसीपी टार्गेट को देखने से पता चलता है कि राज्य के कुल बजट की 50% राशि बैंकों के माध्यम से राज्य में खर्च की जा रही है। अर्थात बैंक भी राज्य के विकास में बराबर के सहयोगी हैं।

उन्होने आगे सभा को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य का गिरता हुये सीडी रेशिओ काफी चिंता का विषय है। उन्होने कहा कि गत वर्ष सितम्बर-20 में राज्य का सीडी रेशिओ 50.04% था, जो कि सितम्बर-21 में घटकर 39.67% हो गया। CD Ratio में यह बहुत बड़ी गिरावट है। उन्होने इस संबंध में कहा कि कोविड महामारी के समय बैंकों के कुल जमा (Deposit) में वृद्धि हुई, किन्तु ऋण प्रवाह (Credit Flow) में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पाई है। राज्य में कोविड महामारी का प्रभाव कम हुआ है और जन-जीवन सामान्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह आशा की जा रही है कि CD Ratio में निकट भविष्य में वृद्धि होगी। उन्होने आगे कहा कि बैंक वार CD Ratio को देखने से पता चलता है कि कुछ बैंक अच्छा कार्य कर रहे है, परंतु कुछ बैंक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे है। उन्होने राज्य के दो प्रमुख बैंकों एसबीआई एवं बीओआई की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुये कहा कि इन दोनों बैंक का CD Ratio राज्य के औसत CD Ratio 39.67% से काफी कम होना चिंता का विषय है। उन्होने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी बैंक, विशेषकर बड़े बैंक, राज्य के विकास मे भागीदारी देंगे।

उन्होने कहा कि राज्य सरकार, राज्य के विकास के लिए कई योजनाएँ बनाती है। इन योजनाओं को सफल करने में बैंकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजना लायी गई, जिसमें राज्य के करीब 9 लाख किसानों को लाभ मिलेगा एवं करीब 4,500 करोड़ का Credit Inflow बैंकों में आयेगा। उन्होने राज्य सरकार द्वारा जारी उद्योग नीति-2021 की जानकारी देते हुये कहा कि इस नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज़ को 25% या 25 करोड़ तक अनुदान (Including Capital Subsidy) दी जा रही है।MSME एवं Large Sector के सभी क्षेत्रों में यह Subsidy दी जा रही है। इसके साथ साथ क्रेडिट में Interest Subsidy भी दी जा रही है।

उन्होने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही **"जोहार योजना"** की जानकारी देते हुये बताया कि इसके द्वारा काफी एफ़पीओ (FPO) का सृजन होगा, जिन्हे आगामी भविष्य मे बैंक-ऋण की आवश्यकता होगी। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं जिसमें राज्य सरकार अनुदान भी दे रही है, उन योजनाओं को बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं ऋण उपलब्ध सुनिश्चित करानी चाहिए।

उन्होने सभा को जानकारी दी कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगले वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बैंकों में डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होने केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही 47 योजनाओं में भी डीबीटी के माध्यम से अनुदान देने की योजना बताई। उन्होने राज्य सरकार के 13 नवंबर, 2021 को आयोजित कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को पेंशन देने की योजना बनायी है, विशेषतः जो Income-Tax Payee नहीं है तथा जिन्हे किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती है। उन्होने अनुमान जताया कि राज्य मे लगभग 14-15 लाख लोगों को सार्वजनिक पेंशन (Universal Pension) योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जिन्हे बैंक द्वारा डीबीटी के माध्यम से ही पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होने केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्टेट नोडल बैंक नियुक्त करने की योजना की जानकारी दी। उन्होने बताया कि यह नियुक्ति स्थायी नहीं होगी। इसमें सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी स्टेट नोडल बैंक के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन अच्छा होने पर उन्हे अगले वर्ष के लिए continue किया जाएगा तथा मूल्यांकन अच्छा नहीं होने पर नए बैंक को (जिनका मूल्यांकन अच्छा होगा) मौका दिया जाएगा। इसमें उन बैंकों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा, जिनका आईटी नेटवर्क एवं सपोर्ट ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ उन्होने बताया कि बैंक और ग्राहक तथा बैंक और सरकारी विभाग के बीच के संबंध को अच्छा करने की आवश्यकता है ताकि स्टेट नोडल बैंक की योजना को सफल बनाया जा सके।

अंत में उन्होने कहा कि जिला स्तर पर DLCC की बैठक नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिए तथा इसमें चर्चा के बाद जो भी निर्णय लिया जाता है, उसकी जानकारी वित्त विभाग को दी जानी चाहिए, साथ ही साथ डीएलसीसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की जानकारी एसएलबीसी के बैठक में दी जानी चाहिए। इसी प्रकार एसएलबीसी की विभिन्न उप-समिति की बैठक के निर्णय के अनुपालन की जानकारी भी एसएलबीसी की बैठक में दी जानी चाहिए तथा इसके अनुपालन में यदि कोई समस्या आती है, तो उसे एसएलबीसी के बैठक में चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

इस सम्बोधन के पश्चात बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री स्वरूप दासगुप्ता को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। सर्वप्रथम श्री दासगुप्ता ने मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों एवं सभा में उपस्थित सभी आगंतुकों का अभिवादन किया। उन्होने सभी स्टेक होल्डेर्स एवं बैंकों से अनुरोध किया कि जो भी मुद्दे एसएलबीसी की इस बैठक में नाबार्ड, आरबीआई एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए है, उन्हे बैंको द्वारा प्राथमिकता देते हुये अनुपालन किया जाना चाहिए।

- उन्होने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड के द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु बैंकों द्वारा अधिक से अधिक कृषि मियादी ऋण (Agriculture Term Loan) दिये जाने का समर्थन किया, जिससे राज्य के CD Ratio में वृद्धि हो सके। उन्होने बताया कि बैंकों द्वारा कार्यशील पूँजी दिये जाने पर उसका

प्रभाव CD Ratio में ऋणी द्वारा निकासी पर निर्भर रहता है, जबकि मियादी ऋण (Term Loan) में ऋण वितरण ऋणी को एक साथ किया जाता है। अत: उन्होने सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुखों से अनुरोध किया कि शाखाएँ कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा Term Loan स्वीकृत करे तथा उन्हे तुरंत संवितरित (Disburse) भी करे।

- उन्होने आरबीआई के जीएम श्री संजीव सिन्हा के बैंक बीसी को निगरानी के सुझाव के संबंध में कहा कि बैंकों को अपने बीसी की नियमित निगरानी करनी चाहिए, साथ उनको hand hold करने, उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके साथ लेन-देन करने वाले ग्राहकों की समस्याओं एवं जरूरतों को समझने की जरूरत है जिससे पूरी प्रक्रिया में सुधार आयेगा।
- उन्होने MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई जीएम के द्वारा सुझाए विंदु का जिक्र करते हुये कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों का Micro Sector में अच्छी उपलब्धि रही है, किन्तु मध्यम एवं लघु क्षेत्र (Medium and Small Sector) में बैंकों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता बताई।
- उन्होने आरबीआई जीएम द्वारा उठाए गए Connectivity Issue का जिक्र करते हुये बताया कि बैंकों को इसके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होने CGTMSE के hybrid-Model के संबंध में बताया कि इसमें ऋणी को ऋण का कुछ भाग CGTMSE Cover एवं कुछ भाग Colleteral Security से Cover करने की छुट होती है। इसके लिए उन्होने उद्योग आधार को जरूरी किए जाने की जानकारी देते हुये बताया कि इससे एमएसएमई फ़ाइनेंस में सुविधा होगी।
- उन्होने CD Ratio में सुधार के लिए बैंकों से अनुरोध किया कि इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। उन्होने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया भी इसके लिए प्रयास कर रही है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे- एग्री इन्फ्रा फ़ंड की जानकारी साझा करें जिससे बैंकों को इसमें फ़ाइनेंस कर अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
- उन्होने बैंकों में डिजिटल लैंडिंग शुरू किए जाने की जानकारी देते हुये बताया कि सभी बैंक इस दिशा में कार्य कर रहें है और आशा की जाती है कि दिसम्बर महीने से बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ प्रोडक्टस की डिजिटल लैंडिंग शुरू कर रही है, फिर अन्य प्रोडक्टस की भी डिजिटल लैंडिंग शुरू कर दी जाएगी। इसमें App Base लैंडिंग भी शुरू किए जाने का प्रावधान है। अन्य बैंक भी इस दिशा में प्रयास कर रहें हैं।
- उन्होने PSB-59 मिनट्स पोर्टल के बारे जानकारी देते हुये बताया कि बैंक ऑफ इंडिया यह प्रयास कर रही है कि इसमें आवेदनकर्ता को Provisional Sanction Letter के साथ-साथ Final Sanction Letter भी उपलब्ध हो सके।
- उन्होने कृषि सचिव के सम्बोधन के संदर्भ में कहा कि जब तक राज्य मे केसीसी आवेदन तथा फ़ाइनेंस के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार नहीं होता है, बैंकों को अपने शाखाओं को केसीसी आवेदन प्राप्ति पर पावती-

रशीद (Acknowledgment Receipt) देने तथा उसको शाखा स्तर पर अच्छे से रख-रखाव के लिए निर्देशित करने चाहिए, जिससे आवेदनों का सही समय पर निष्पादन किया जा सके तथा उनकी proper monitoring की जा सके। उन्होने कहा कि केसीसी के आवेदनकर्ता बहुत छोटे किसान होते हैं। उन्हे बैंकों से सहयोग की जरूरत है। इसके अतिरिक्त उन्होने कृषि सचिव द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुये कहा कि बैंकों को इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है।

- उन्होने प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग के श्री अजय कुमार सिंह के वक्तव्य का संदर्भ लेते हुये कहा कि राज्य का CD Ratio का कम होना या गिरना एक चिंता का विषय है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि झारखंड में सभी बैंकों के सहयोग से इसमें समयबद्ध तरीके से वृद्धि की जा सके। उन्होने आगे कहा कि यदि बैंक के पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स फ़ाइनेंस के लिए मिलते हैं, तो बैंक उसमें जरूर फ़ाइनेंस करेंगे। उन्होने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया भी अधिक से अधिक ऋण देकर अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते है, जिससे बैंक का CD Ratio बढ़ोतरी हो सके।
- उन्होने प्रधान सचिव ,वित्त, राज्य सरकार द्वारा बताई गयी Interest Subsidy योजनाओं तथा FPOs के फ़ाइनेंस के संबंध में कहा कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन सभी योजनाओं में ऋण प्रदान करने में सहयोग किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त उन्होने राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराये जाने की योजना का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होने केंद्र सरकार के स्टेट नोडल बैंक की नियुक्ति की योजना का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होने बताया कि इसमें सभी बैंकों के लिए काम करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा इसके साथ ही उन्होने बैंकों एवं राज्य सरकार में उचित समन्वय रखने की जरूरत का समर्थन किया साथ ही साथ डीएलसीसी की बैठक एवं एसएलबीसी की सभी उप-समितियों की बैठक के लंबित मुद्दों को एसएलबीसी की बैठक में चर्चा किए जाने को सही बताया तथा कहा कि इससे इन बैठकों का महत्व बढ़ जाएगा।

अंत में उन्होने कहा कि झारखंड कोविड के बाद प्रगति की ओर अग्रसर है एवं सभी बैंकों, नाबार्ड, आरबीआई एवं राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।

इस सम्बोधन के पश्चात बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा एसएलबीसी, झारखंड के अध्यक्ष श्री अतनु कुमार दास को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया।

श्री दास ने सर्वप्रथम COVID-19 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हेतु बैंकों द्वारा गए कार्यों की सराहना की एवं सभी को धन्यवाद दिया। तत्पश्चात झारखंड राज्य के CD Ratio पर चिंता जाहीर करते हुये श्री दास ने बताया की विभिन्न Parliamentary committee के मंचों पर बहुत से जन प्रतिनिधियों द्वारा यह मुद्दा निरंतर उठाया जाता है की

झारखंड राज्य में बैंक की शाखाओं में CD Ratio हेतु पर्याप्त जागरूकता नहीं है, विभिन्न योजनाओ के तहत आए आवेदन बहुत समय के लिए शाखा में लंबित रहते हैं जो की एक सोचनीय विषय है।

उन्होने राज्य मे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंकों की सराहना की और बैंको को आगे भी इस क्षेत्र में सभी पात्र ग्राहकों को आच्छादित करने की अपील की। उन्होने बैंकों को महिला एसएचजी के ऋण को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होने एसएलबीसी और सभी बैंकों को आपस में उचित तालमेल रखने पर ज़ोर दिया। साथ ही उन्होने सभी बैंको को अपनी कार्यनीतियों पर पुनः आत्ममंथन करने का अनुरोध किया।

उन्होने अक्तूबर माह में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी बैठक का ज़िक्र करते हुए बताया कि उपरोक्त बैठक मे समस्त बैंकों के राज्य प्रमुखों से बैंकों के प्रदर्शन में समुचित सुधार हेतु निवेदन किया था। उन्होने कहा कि सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष के बचे हुए चार महीनों में अपना प्रदर्शन बेहतर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि सभी बैंक कुछ महत्वपूर्ण योजना पर ही ध्यान केन्द्रित करें और इनके क्रियान्वयन का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही प्रदर्शन मे अपेछित सुधार होगा। इससे बैंकों का वैयक्तिक व्यवसाय तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ सम्मिलित रूप से राज्य के CD Ratio में भी सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि बैंक शाखाओं में जागरूकता की कमी में सुधार हेतु राज्य प्रमुखों को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं एवं एसएलबीसी द्वारा दिये गए सभी दिशानिर्देशों को यथासमय सभी शाखाओं तक प्रेषित करने का आग्रह किया साथ ही बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों का सभी शाखाओं के शाखा प्रबन्धक से उचित समन्वय होने की आवश्यकता बतायी। इसके उपरांत उन्होने जिलों में DCC/DLRC बैठकों के समय पर सम्पन्न न होने पर चिंता जताई तथा सभी एलडीएम से DCC बैठकों का यथासमय आयोजन सुनिश्चित करने का निवेदन किया। उन्होने कहा कि जो भी कार्ययोजना एसएलबीसी/डीसीसी/ बीएलबीसी बैठक में बनाई जाती हैं उन सभी के लिए एक समयसीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है जिससे सभी कार्य समय पर सम्पन्न हो और राज्य में प्रगति देखी जा सके। उन्होने बताया कि छोटे छोटे समयबद्ध लक्ष्य का निर्धारण तथा समय समय पर उपलब्धियों का आंकलन/ समीक्षा करना काफी कारगर साबित हो सकता है। श्री दास ने बैंकों द्वारा राज्य के आदिवासी जनसंख्या को अधिक से अधिक बैंकों से जोड़ने और उन्हे ऋण प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया।

तत्पश्चात उन्होने एसएलबीसी टीम से आगामी SLBC की बैठक में Action Taken Report को दो भागों में दर्शाने की बात कही जिसके पहले भाग में वो सभी कार्य दर्शाए जाएँ जो पूरे किए जा चुके हैं और दूसरे भाग में सभी कार्य समयसीमा के साथ दर्शाए जाएँ जो कि अभी पूर्ण नहीं हैं। साथ ही साथ श्री दास ने राज्य के सभी बैंकों के लिए "मिशन दस कदम" का प्रस्ताव भी रखा जिसके माध्यम से किन्ही दस केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मासिक लक्ष्य निर्धारित कर एक विशेष अभियान चलाया जा सके। उन्होने एसएलबीसी से आग्रह किया कि मिशन दस कदम हेतु सभी बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को सफल बनाने का हरसंभव प्रयास करें।

अंत में उन्होने सभी बैंकों को अगली एसएलबीसी की बैठक तक सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आग्रह करते हुए शुभकामनायें दी।

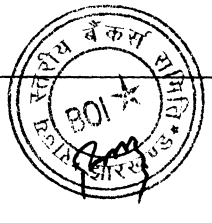

## व्यवसाय सत्र

सभा के द्वितीय भाग मे एसएलबीसी के वरिस्ठ प्रबन्धक श्री विभव कुमार ने व्यवसायिक सत्र का संचालन किया। Agenda wise परिचर्चा के दौरान माननीय सभाअध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य सदस्यों द्वारा निम्न प्रमुख विंदुओ को सदस्य बैंको के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- ✓ SWOT Analysis पर चर्चा के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने कहा कि अगली एसएलबीसी की बैठक के पहले एसएलबीसी को आगामी तिमाही में कम प्रदर्शन वाले बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए तथा एसएलबीसी को Small Finance Banks का मार्गदर्शन एवं सहयोग (Hand Holding) करने की आवश्यकता है।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति पर चर्चा के दौरान प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग से श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन 14 जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति लंबित है, उसपर शीघ्र की नियुक्ति की जाएगी।
- ✓ एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में एससी/एसटी वर्ग को ऋण प्रवाह की समीक्षा पर चर्चा के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा एसएलबीसी, झारखंड के अध्यक्ष श्री अतनु कुमार दास ने बताया कि नवम्बर महीने में आयोजित नेशनल कमिशन फॉर Schedule Tribe के सदस्यों के साथ इस संदर्भ में एक बैठक हुई थी, जहाँ यह निर्णय लिया गया था कि देश के जिन जिलों में Schedule Tribes की संख्या ज्यादा है, वहाँ बैंकों को विशेष ड्राइव चलाकर इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। उन्होनेकहा कि झारखंड में बहुत जिलें ऐसे हैं, जहाँ Schedule Tribes की संख्या अधिक है और उन्होने राज्य के सभी बैंक प्रमुखों को इस दिशा में एक कार्यनीति बनाकर काम करने हेतु आग्रह किया।
- ✓ पीएम स्वनिधि की प्रगति की वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे सभा को बताया गया कि राज्य की कुल उपलब्धि अभी तक करीब 56% के पास है तथा Urban Local Bodies (ULBs) मे पंजीकृत पथ-बिक्रेताओं की सूची एवं संख्या लेकर आवेदन सृजन किए जा सकते हैं।
- ✓ एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में Yes Bank द्वारा दिये गए 43,000 बीसी की सूची पर चर्चा करते हुये उनसे एसएलबीसी के दिये गए फ़ारमैट में Block-Wise Village-Wise एवं पंचायत-वार सूची उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।
- ✓ कृषि विभाग से केसीसी आवेदनों की बैंकवार-शाखावार सूची उपलब्ध कराने के विषय पर सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने कहा कि एसएलबीसी के पास उपलब्ध 5.13 लाख केसीसी आवेदनों की बैंकवार एवं शाखावार सूची कृषि विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया। जिससे कृषि विभाग अपने रिपोर्ट से मिलान (Reconciliation) कर आवेदनों को निस्पदित किया जा सके। साथ ही सचिव ने कुछ बैंकों द्वारा एक लाख रुपए

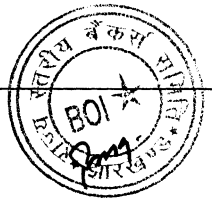

तक केसीसी के फ़ाइनेंस में एलपीसी माँगे जाने पर आपत्ति जताते हुये कहा कि बैंकों को अपनी शाखाओं को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

- ✓ एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में CD Ratio पर चर्चा के दौरान एसबीआई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि एसबीआई का सीडी रेशिओ सितम्बर-2021 में घटकर 27.07% हो गया है, जबकि सितम्बर-2020 की तुलना में सितम्बर-2021 में बैंक के डिपॉज़िट में 5,600 करोड़ तथा कुल अग्रिम में 3,300 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होने आगे बताया कि एसबीआई के द्वारा CCG एवं CAG श्रेणी में दिये गए 15,000 करोड़ के अग्रिम को रेपोर्टिंग फ़ारमैट में परिवर्तन के कारण Credit as per Place of Utilization में दिखाने के वजह से वह एसबीआई के सीडी रेशिओ में प्रदर्शित नहीं हो सकता है। उन्होने आगे कहा कि एसबीआई द्वारा सीडी रेशिओ नियमित वृद्धि हेतु प्रयास किया जा रहा है।
- ✓ सीएफ़एल प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान इंडियन बैंक के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि उनके बैंक द्वारा झारखंड में 4 सीएफ़एल स्थापित किए जाने है तथा ये सभी सीएफ़एल दिसम्बर-2021 तक स्थापित कर दिये जाएंगे।
- ✓ व्यवसायिक सत्र के चर्चा के दौरान प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग से श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि एसएलबीसी की बैठक में केवल उन्ही मुद्दों चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर सभा का अनुमोदन की आवश्यकता है या जिन मुद्दे का निष्पादन एसएलबीसी की उप-समिति नहीं हो पा रहे है।
- ✓ इस क्रम में, सभा को जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू किया गया है, जिसमें दिनांक 24.04.2020 से नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि के सीमांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2021 को प्राप्त पत्र के आलोक मे बताया गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को राज्य के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनकी आवासीय संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में लाभ उठाकर उनकी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने हेतु, पंचायती राज मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि बैंकों को एसएलबीसी की बैठक में इस विषय पर परिचर्चा करनी है। इस संबंध में, सभा में यह निर्णय लिया गया है कि इसके लिए Land and Revenue विभाग, झारखंड सरकार को आधिकारिक सूचना दी जाए एवं प्रतिलिपि योजना-सह-वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।

अंत में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बिनोद कुमार पट्टनायक ने धन्यवाद प्रस्ताव में एसएलबीसी की 77वीं बैठक में शामिल होने के लिए सभी स्टेक होल्डेर्स का धन्यवाद दिया।

( बिक्रम केशरी मिश्र )
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| क्रम संख्या | विषय | विभाग द्वारा | विवरण | संबन्धित उप समिति | कृत कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | पशुपालन और मत्स्य पालन के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने हेतु साप्ताहिक जिला स्तरीय विशेष केसीसी अभियान | कृषि विभाग | भारत सरकार के दिशानिर्देसानुसार पशुपालन और मत्स्य पालन के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने हेतु साप्ताहिक जिला स्तरीय विशेष केसीसी अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत सभी जिलों में प्रत्येक शुक्रवार को विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि अभियान की सफलता हेतु अग्रणी ज़िला प्रबन्धको को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।<br><br>राज्य में सितम्बर, 2021 की रिपोर्टिंग के अनुसार बैंकों द्वारा लगभग 13 लाख केसीसी जारी किये गए है, जबकि राज्य में कुल 30 लाख पंजीकृत पीएम किसान लाभूक हैं एवं कुल किसानों की संख्या लगभग 50 लाख है। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि कम-से-कम पीएम किसान लाभूकों को केसीसी अवश्य उपलब्ध कराया जाए।<br><br>केसीसी आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है, तो उसे जिला कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ठीक करवाने हेतु विशेष बीएलबीसी बैठक आयोजित कर उसमें चर्चा करें। इसी प्रकार, उन्होने डेयरी एवं फिशेरी किसानों को केसीसी जारी करने के आकड़े देखकर कहा कि बैंकों द्वारा आवेदन स्वीकृति की तुलना में निरस्त किए जाने वाले आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होने डेयरी के अंतर्गत झारखंड मिल्क फ़ैडरेशन से जुड़े किसानों के केसीसी आवेदनों के रिजेक्ट किए जाने पर चिंता जताते हुये कहा कि ये किसान जेएमएफ़ को दुग्ध की आपूर्ति करते हैं और जेएमएफ़ | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | सभी बैंक / एलडीएम |

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | द्वारा दुग्ध की कीमत का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।इस प्रकार के खातो मे बैंकों को रिकवरी मे कम परेशानी होगी अतः इन आवेदनों के निष्पादन हेतु बैंको को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होने बैंक प्रमुखों से अनुरोध किया कि केवल एक अधिकारी या कम स्टाफ वाले शाखाओं में लंबित आवेदनों को Centralized Mechanism द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। | | |
| 02 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | नाबार्ड | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रवाह हेतु आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के कुल अग्रिम के सापेक्ष कृषि ऋण कम से कम 18% होना चाहिए, जबकि झारखंड राज्य में केवल 14.46% ही है। विगत वर्ष के सितम्बर तिमाही के सापेक्ष में इस वर्ष की सितंबर तिमाही में बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा लेकिन अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। राज्य के कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु बैंकों द्वारा अधिक से अधिक कृषि मियादी ऋण (Agriculture Term Loan) दिये जाने की जरूरत है, जिससे राज्य के CD Ratio में वृद्धि हो सके। | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 03 | Farmer Producer Organisations | नाबार्ड | राज्य के किसानों की फार्म आय किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisations) के माध्यम से बढ़ाने हेतू अधिक से अधिक FPOs को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।FPO ऋण की सुरक्षा हेतू ऋण गारंटी योजना भी उपलब्ध है जिसका उपयोग FPO क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को करना चाहिए। | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | सभी बैंक / एलडीएम |

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | झारखंड कृषि ऋण माफी | कृषि विभाग | झारखंड कृषि ऋण माफी के संदर्भ में बताया गया कि ऋण माफी हेतु बैंकों द्वारा कुल 9.06 लाख पात्र खातों में केवल 5.80 केसीसी खातों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कृषि विभाग ने बैंकों से अनुरोध किया कि इस योजना हेतु सरकार के पास 1,500 करोड़ की राशि उपलब्ध है एवं जिस बैंक का डाटा पोर्टल पर जल्द अपलोड होगा उसे पहले योजना का लाभ दिया जाएगा। | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | संबन्धित बैंक |
| 05 | एग्री इन्फ्रा फ़ंड | कृषि विभाग | एग्री इन्फ्रा फ़ंड की उपलब्धि की चर्चा करते हुये बताया गया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में झारखंड राज्य की उपलब्धि नगण्य है, जबकि राज्य का लक्ष्य काफी अधिक है इस संदर्भ में बैंकों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक जिले मे एग्री इन्फ्रा फ़ंड योजना के अंतर्गत वितीय वर्ष मे कम से कम एक ऋण स्वीकृति अवश्य करें। | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | संबन्धित बैंक |
| 06 | राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि क्षेत्र | कृषि विभाग | सभा को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुये बताया गया कि विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा 40% से 90% तक अनुदान दिया जाता है,अतः बैंको को आगे आकर शेष राशि को बैंक द्वारा फ़ाइनेंस किया जा सकता है। | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 07 | केसीसी फ़ाइनेंस में एलपीसी की आवश्यकता | कृषि सचिव | कृषि सचिव ने कुछ बैंकों द्वारा एक लाख रुपए तक केसीसी के फ़ाइनेंस में एलपीसी माँगे जाने पर आपत्ति जताते हुये कहा कि बैंकों को अपनी शाखाओं को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए। | कृषि एवं संबद्ध उपसमिति | सभी बैंक / एलडीएम |

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखंड

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | बीसी ट्रैंज़ैक्शन | भारतीय रिजर्व बैंक | आरबीआई ने एईपीएस )AePS) अनियमितताओं के रोकथाम हेतु बैंकों के बीसी आउटलेट्स पर किए जा रहे लेनदेन की निगरानी के लिए एक परिभाषित ढांचे की आवश्यकता बतायी। साथ ही बीसी के माध्यम से किए जा रहे लेनदेन की मात्रा का आकलन किया जाना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई लेनदेन दोहराया तो नहीं जा रहा है साथ ही सीएसपी पर ग्राहक द्वारा किए गए वास्तविक लेनदेन की पावती )Receipt) उत्पन्न की जा रही है या नहीं। तकनीकी कारणों से बीसी के कामकाज को प्रभावित होने के रोकथाम हेतु उचित कनेक्टिविटी की आवश्यकता भी बतायी । उन्होने एसएलबीसी को सलाह दी कि इस विषय से संबन्धित उप-समिति मे इस संबंध में प्रत्येक बैंक द्वारा उपलब्ध संरचना की जांच करे एवं SLBC बैंकों के बीसी पॉइंट्स की निगरानी प्रक्रिया को आगामी बैठक में शामिल करे। | वित्तीय समावेशन उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 09 | Yes Bank द्वारा दिये गए 43,000 बीसी की सूची | एसएलबीसी | एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में Yes Bank द्वारा दिये गए 43,000 बीसी की सूची पर चर्चा करते हुये उनसे एसएलबीसी के दिये गए फ़ारमैट में Block-Wise Village-Wise एवं पंचायत-वार सूची उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया। | वित्तीय समावेशन उप समिति | Yes Bank |
| 10 | हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र | भारतीय रिजर्व बैंक | हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र COVID19 महामारी के कारण तनावग्रस्त है और ऐसे उत्पादों की मांग में हुये इजाफे के लिए संस्थागत ऋण सहायता की आवश्यकता है । बैंक इस क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर | ऋण जमा अनुपात उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम/ एसएलबीसी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | संबन्धित उप-समिति में चर्चा करते हुये अगली एसएलबीसी बैठक में प्रस्तुत करने की बात की। | | |
| 11 | 40 प्रतिशत से कम सीडी अनुपात | भारतीय रिजर्व बैंक | झारखंड राज्य के 24 में से 16 जिलों के पिछले आधे दशक के दौरान लगातार 40 प्रतिशत से कम सीडी अनुपात की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई रांची ने इसके कारणों के आकलन हेतु जिलों में जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया है। निष्कर्षों के अवलोकन से पता चलता है कि भूमि रिकॉर्ड के अद्यतन की कमी, बैंकों के ग्राहकों द्वारा व्यावसायिक रिकॉर्ड बनाए रखने में असमर्थता, आईटीआर/जीएसटी दाखिल करते समय अंडर-रिपोर्टिंग तथा राज्य में माइग्रेशन, राज्य के कम सीडी अनुपात के कुछ प्रमुख कारण हैं। विस्तृत निष्कर्ष शीघ्र ही एसएलबीसी के संयोजक के साथ साझा किए जाएंगे ताकि उप-समिति इन निष्कर्षों पर विचार-विमर्श करके प्रत्येक जिले के हितधारकों के साथ सीडी अनुपात को बढ़ाने में संबंधित भूमिका निभाने का आग्रह करे। उप-समिति के विचार-विमर्श का परिणाम अगली बैठक में एसएलबीसी को दिया जा सकता है। | ऋण जमा अनुपात उप समिति | एसएलबीसी |
| 12 | CD Ratio | वित्त सचिव | CD Ratio के संदर्भ मे राज्य के दो प्रमुख बैंकों एसबीआई एवं बीओआई की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुये वित्त सचिव ने कहा कि इन दोनों बैंक का CD Ratio राज्य के औसत CD Ratio 39.67% से काफी कम होना चिंता का विषय है। उन्होने उम्मीद | ऋण जमा अनुपात उप समिति | एसबीआई एवं बीओआई |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | जताई कि राज्य के सभी बैंक, विशेषकर बड़े बैंक, राज्य के विकास मे भागीदारी देंगे। | | |
| 13 | एग्री इन्फ्रा फ़ंड | कार्यकारी निदेसक,बैंक ऑफ इंडिया | CD Ratio में सुधार के लिए बैंकों से अनुरोध किया गया कि इसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे- एग्री इन्फ्रा फ़ंड की जानकारी साझा करें जिससे बैंकों को इसमें फ़ाइनेंस कर अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़ाने का अवसर मिलेगा। | ऋण जमा अनुपात उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 14 | CD Ratio | प्रबंध निदेसक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | CD Ratio पर चिंता जाहीर करते हुये श्री दास ने बताया की विभिन्न Parliamentary committee के मंचों पर बहुत से जन प्रतिनिधियों द्वारा यह मुद्दा निरंतर उठाया जाता है की झारखंड राज्य में बैंक की शाखाओं में CD Ratio हेतु पर्याप्त जागरूकता नहीं है, विभिन्न योजनाओ के तहत आए आवेदन बहुत समय के लिए शाखा में लंबित रहते हैं जो की एक सोचनीय विषय है। | ऋण जमा अनुपात उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 15 | एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिश | भारतीय रिजर्व बैंक | एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स में सिफारिश के अनुसार एमएसएमई के वित्तपोषण में अपेक्षा के अनुरूप राज्य में बैंकों का प्रदर्शन काफी नीचे रहा है । इस क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता बतायी। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा CGTMSE कवरेज और उद्योग आधार पंजीकरण के अभाव में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के वर्गीकरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता का ज़िक्र किया । श्री | एमएसएमई उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम/एसएलबीसी |

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सिन्हा ने बताया कि संबंधित उप-समिति बैंकों के उपरोक्त मुद्दों और चिंताओं पर विचार-विमर्श कर सकती है और इस वर्ग को ऋण देने में प्राप्त सुझावों को आगामी एसएलबीसी की बैठक मे रखा जा सकता है। | | |
| 16 | उद्योग नीति-2021 | वित्त सचिव | राज्य सरकार द्वारा जारी उद्योग नीति-2021 की जानकारी देते हुये कहा कि इस नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज़ को 25% या ) करोड़ तक अनुदान 25Including Capital Subsidy) दी जा रही है।MSME एवं Large Sector के सभी क्षेत्रों में यह Subsidy दी जा रही है। इसके साथ साथ क्रेडिट में Interest Subsidy भी दी जा रही है। बैंको को इस संबंध मेMSME एवं Large Sector को सुविधा देनी चाहिए। | एमएसएमई उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 17 | मध्यम एवं लघु क्षेत्र (Medium and Small Sector) | कार्यकारी निदेसक,बैंक ऑफ इंडिया | उन्होने MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई जीएम के द्वारा सुझाए विंदु का जिक्र करते हुये कार्यकारी निदेसक ,बीओआई ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के Micro Sector में बैंकों की अच्छी उपलब्धि रही है, किन्तु मध्यम एवं लघु क्षेत्र (Medium and Small Sector) में बैंकों को काफी कुछ करने की आवश्यकता बताई। | एमएसएमई उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 18 | CGTMSE Hybrid-Model | | CGTMSE के hybrid-Model के संबंध में कार्यकारी निदेसक ,बीओआई ने बताया कि इसमें ऋणी को ऋण का कुछ भाग CGTMSE Cover एवं कुछ भाग Colleteral Security से Cover करने की छूट होती है। इसके लिए उन्होने उद्योग आधार को | एमएसएमई उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | जरूरी किए जाने की जानकारी देते हुये बताया कि इससे एमएसएमई फ़ाइनेंस में सुविधा होगी। | | |
| 19 | जोहार योजना | वित्त सचिव | राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही "जोहार योजना" की जानकारी देते हुये वित्त सचिव ने बताया कि इसके द्वारा राज्य मे काफी एफ़पीओ (FPO) का सृजन होगा, जिन्हे आगामी भविष्य मे बैंक-ऋण की आवश्यकता होगी। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं जिसमें राज्य सरकार अनुदान भी दे रही है, उन योजनाओं को बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए। | एसएचजी उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 20 | महिला एसएचजी को ऋण | प्रबंध निदेसक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | राज्य मे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंकों की सराहना की और बैंको को आगे भी इस क्षेत्र में सभी पात्र ग्राहकों को आच्छादित करने की अपील की। उन्होने बैंकों को महिला एसएचजी के ऋण को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होने एसएलबीसी और सभी बैंकों को आपस में उचित तालमेल रखने पर ज़ोर दिया। साथ ही उन्होने सभी बैंको को अपनी कार्यनीतियों पर पुनः आत्ममंथन करने का अनुरोध किया। | एसएचजी उप समिति | सभी बैंक / एलडीएम |
| 21 | RSETI क्रेडिट लिंकेज | भारतीय रिजर्व बैंक | RSETI प्रशिक्षुओं के संबंध मे आरबीआई ने बताया कि क्रेडिट लिंकेज के लिए TAT 6 महीने के भीतर 15% था और 6 महीने या उससे अधिक के लिए 9% था। TAT को कम करने के लिए, एसएलबीसी, संयोजक द्वारा विभिन्न बैंकों में आवेदनों की प्रगति | Rseti उप समिति | एसएलबीसी |

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पर नज़र रखने हेतु एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने की आवश्यकता बतायी, जिससे प्रगति की जानकारी आगामी एसएलबीसी की बैठक में दी जा सके। | | |
| 22 | सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति | प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग | राज्य सरकार द्वारा सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति पर चर्चा के दौरान प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग से श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन 14 जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति लंबित है, उसपर शीघ्र की नियुक्ति की जाएगी। | एनपीए उप समिति | राज्य सरकार |
| 23 | एसएलबीसी की बैठक मे परिचर्चा | वित्त सचिव | श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि एसएलबीसी की बैठक में केवल उन्ही मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर सभा के अनुमोदन की आवश्यकता है या जिन मुद्दों का निष्पादन एसएलबीसी की उप-समिति द्वारा नहीं हो पा रहा है। | एसएलबीसी परिचालन उप समिति | एसएलबीसी |
| 24 | स्टार्ट-अप के लिए उचित नीतियां | भारतीय रिजर्व बैंक | श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य ने स्टार्ट-अप संबंधित मापदंडों पर काफी अच्छा काम किया जैसे- Policy implementation, Angel and Venture Funding, Simplified Regulation, Awareness and Outreach. संबंधित विभाग इन विषयों हेतु एक पोर्टल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे स्टार्ट-अप और वेंचर कैपिटलिस्ट को एक साथ लाकर त्वरित कार्रवाई हेतु एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध हो सके। जिससे प्राप्त इनपुट से राज्य में Start-Up के लिए उचित नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। | ***** | संबन्धित विभाग |
| 25 | डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट | भारतीय रिजर्व बैंक | आरबीआई ने 18 नवंबर, 2021 को अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्स के जरिए कर्ज देने सहित डिजिटल लेंडिंग पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी की है जिसके लिए सभी | ***** | एसएलबीसी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्टेक होल्डेर्स से सुझाव मांगा गया है। उन्होने एसएलबीसी संयोजक बैंक से राज्य सरकार तथा सभी संबन्धित हितधारकों से परामर्श के बाद आरबीआई को अपनी टिप्पणियां 31 दिसम्बर,2021 तक प्रस्तुत करने का आग्रह किया। | | |
| 26 | वित्तीय सेवाए विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाए | एसएलबीसी | पिछली तिमाही से, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान वित्तीय सेवाए विभाग, भारत सरकार द्वारा निरंतर अंतराल पर समीक्षा की जा रही है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना , मुद्रा, स्टैंडअप इंडिया, केसीसी, PMSVANidhi, PMEGP इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा आत्मानिर्भर भारत योजना जैसे AIF, AHIF, PMFME, 2% Interest Subvention Scheme, Special Liquidity Scheme एवं Ethanol Blending Scheme शामिल हैं। इस संबंध में, बैंकों को सभी योजनाओं के तहत लक्ष्य दिए गए हैं और एसएलबीसी द्वारा समय-समय पर क्रियान्वयन हेतु उचित निर्देश भी दिए जा रहे हैं। | **** | सभी सदस्य बैंक/एलडीएम |
| 27 | जन सुरक्षा योजनाओं हेतू Saturation Drive | एसएलबीसी | डीएफएस, भारत सरकार द्वारा जन सुरक्षा योजनाओं हेतू 2 अक्टूबर, 2021 से Saturation Drive शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा साप्ताहिक प्रदर्शन एसएलबीसी को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे एसएलबीसी द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार को डीएफएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में, भारत सरकार द्वारा एक Special Campaign भी शुरू किया गया | **** | सभी सदस्य बैंक/एलडीएम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | है, जिसके अनुसार बैंकों को दिसंबर 2021 तक 18-21 वर्ष के सभी युवाओं को PMJDY खातों से जोड़ना है। | | |
| 28 | डीबीटी के माध्यम से अनुदान | वित्त सचिव | भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगले वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बैंकों में डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होने केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही 47 योजनाओं में भी डीबीटी के माध्यम से अनुदान देने की योजना बताई। उन्होने राज्य सरकार के 13 नवंबर, 2021 को आयोजित कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को पेंशन देने की योजना बनायी है, विशेषतः जो Income-Tax Payee नहीं है तथा जिन्हे किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती है। उन्होने अनुमान जताया कि राज्य मे लगभग 14-15 लाख लोगों को सार्वजनिक पेंशन (Universal Pension) योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जिन्हे बैंक द्वारा डीबीटी के माध्यम से ही पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। | ***** | सभी बैंक / एलडीएम |
| 29 | स्टेट नोडल बैंक की नियुक्ति | वित्त सचिव | वित्त सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्टेट नोडल बैंक नियुक्त करने की योजना की जानकारी दी। उन्होने बताया कि यह नियुक्ति स्थायी नहीं होगी। इसमें सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी स्टेट नोडल बैंक के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन अच्छा होने पर उन्हे अगले वर्ष के लिए continue | ***** | सभी बैंक / एलडीएम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | किया जाएगा तथा मूल्यांकन अच्छा नहीं होने पर नए बैंक को जिनका मूल्यांकन अच्छा होगा)) भी मौका दिया जाएगा। इसमें उन बैंकों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा, जिनका आईटी नेटवर्क एवं सपोर्ट ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ उन्होने बताया कि बैंक और ग्राहक तथा बैंक और सरकारी विभाग के बीच के संबंध को अच्छा करने की आवश्यकता है ताकि स्टेट नोडल बैंक की योजना को सफल बनाया जा सके। | | |
| 30 | जिला स्तर पर DLCC की निरंतर बैठक | वित्त सचिव | वित्त सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्टेट नोडल बैंक नियुक्त करने की योजना की जानकारी दी। उन्होने बताया कि यह नियुक्ति स्थायी नहीं होगी। इसमें सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी स्टेट नोडल बैंक के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन अच्छा होने पर उन्हे अगले वर्ष के लिए continue किया जाएगा तथा मूल्यांकन अच्छा नहीं होने पर नए बैंक को (जिनका मूल्यांकन अच्छा होगा) भी मौका दिया जाएगा। इसमें उन बैंकों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा, जिनका आईटी नेटवर्क एवं सपोर्ट ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ उन्होने बताया कि बैंक और ग्राहक तथा बैंक और सरकारी विभाग के बीच के संबंध को अच्छा करने की आवश्यकता है ताकि स्टेट नोडल बैंक की योजना को सफल बनाया जा सके। | **** | सभी बैंक / एलडीएम |

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | एसएलबीसी की बैठक में नाबार्ड, आरबीआई एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए मुद्दे | कार्यकारी निदेसक,बैंक ऑफ इंडिया | सभी स्टेक होल्डेर्स एवं बैंकों से अनुरोध किया कि एसएलबीसी की बैठक में नाबार्ड, आरबीआई एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए मुद्दों को बैंको द्वारा प्राथमिकता देते हुये अनुपालन किया जाना चाहिए। | ***** | सभी बैंक / एलडीएम |
| 32 | बैंकों के प्रदर्शन में समुचित सुधार | प्रबंध निदेसक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | अक्तूबर माह में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी बैठक का ज़िक्र करते हुए श्री दास ने बताया कि उपरोक्त बैठक मे समस्त बैंकों के राज्य प्रमुखों से बैंकों के प्रदर्शन में समुचित सुधार हेतु निवेदन किया था। उन्होने कहा कि सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष के बचे हुए चार महीनों में अपना प्रदर्शन बेहतर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि सभी बैंक कुछ महत्वपूर्ण योजना पर ही ध्यान केन्द्रित करें और इनके क्रियान्वयन का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही प्रदर्शन मे अपेछित सुधार होगा। इससे बैंकों का वैयक्तिक व्यवसाय तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ सम्मिलित रूप से राज्य के CD Ratio में भी सुधार होगा। | ****** | सभी बैंक / एलडीएम |
| | | | श्री दास ने राज्य के बैंक प्रमुखों से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं एवं एसएलबीसी द्वारा दिये गए सभी दिशानिर्देशों को यथासमय सभी शाखाओं तक प्रेषित करने का आग्रह किया साथ ही बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों का सभी शाखाओं के शाखा प्रबन्धक से उचित समन्वय होने की आवश्यकता बतायी। | ***** | सभी बैंक / एलडीएम |

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | आदिवासी जनसंख्या को ऋण | प्रबंध निदेसक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | श्री दास ने बैंकों द्वारा राज्य के आदिवासी जनसंख्या को अधिक से अधिक बैंकों से जोड़ने और उन्हे ऋण प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया। | ****** | सभी बैंक / एलडीएम |
| 34 | "मिशन दस कदम" | प्रबंध निदेसक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | श्री दास ने एसएलबीसी टीम से आगामी SLBC की बैठक में Action Taken Report को दो भागों में दर्शाने की बात कही जिसके पहले भाग में वो सभी कार्य दर्शाए जाएँ जो पूरे किए जा चुके हैं और दूसरे भाग में वह सभी कार्य समयसीमा के साथ दर्शाए जाएँ जो कि अभी पूर्ण नहीं हैं। साथ ही साथ श्री दास ने राज्य के सभी बैंकों के लिए "मिशन दस कदम" का प्रस्ताव भी रखा जिसके माध्यम से किन्ही दस केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मासिक लक्ष्य निर्धारित कर एक विशेष अभियान चलाया जा सके। | ***** | सभी बैंक / एलडीएम |
| 35 | कम प्रदर्शन वाले बैंकों हेतु SWOT Analysis | आरबीआई | SWOT Analysis पर चर्चा के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने कहा कि अगली एसएलबीसी की बैठक के पहले एसएलबीसी को आगामी तिमाही में कम प्रदर्शन वाले बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए तथा एसएलबीसी को Small Finance Banks का मार्गदर्शन एवं सहयोग (Hand Holding) करने की आवश्यकता है। | ****** | संबन्धित बैंक |

# 77वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृत कार्यवाही रिपोर्ट

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | एससी/एसटी वर्ग को ऋण प्रवाह की समीक्षा | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में एससी/एसटी वर्ग को ऋण प्रवाह की समीक्षा पर चर्चा के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा एसएलबीसी, झारखंड के अध्यक्ष श्री अतनु कुमार दास ने बताया कि नवम्बर महीने में आयोजित नेशनल कमिशन फॉर Schedule Tribe के सदस्यों के साथ इस संदर्भ में एक बैठक हुई थी, जहाँ यह निर्णय लिया गया था कि देश के जिन जिलों में Schedule Tribes की संख्या ज्यादा है, वहाँ बैंकों को विशेष ड्राइव चलाकर इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। | ***** | सभी बैंक / एलडीएम |
| 37 | पीएम स्वनिधि की प्रगति | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | पीएम स्वनिधि की प्रगति की वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे सभा को बताया गया कि राज्य की कुल उपलब्धि अभी तक करीब 56% के पास है तथा Urban Local Bodies (ULBs) मे पंजीकृत पथ-बिक्रेताओं की सूची एवं संख्या लेकर आवेदन सृजन किए जा सकते हैं। | ****** | सभी बैंक / एलडीएम |
| 38 | स्वामित्व योजना | एसएलबीसी | भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू किया गया है, जिसमें दिनांक 24.04.2020 से नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि के सीमांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2021 को प्राप्त पत्र के आलोक मे बताया गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को राज्य के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनकी आवासीय संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के | ******* | राजस्व एवं भूमि विभाग |

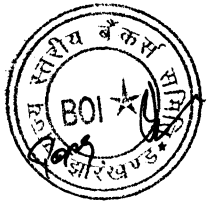

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में लाभ उठाकर उनकी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने हेतु, पंचायती राज मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि बैंकों को एसएलबीसी की बैठक में इस विषय पर परिचर्चा करनी है। इस संबंध में, सभा में यह निर्णय लिया गया है कि इसके लिए Land and Revenue विभाग, झारखंड सरकार को आधिकारिक सूचना दी जाए एवं प्रतिलिपि योजना-सह-वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए। | | |

| *LIST OF PARTICIPANTS IN 77th STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE, JHARKHAND (MEETING HELD ON 22.11.2021)* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **S.N** | **NAME OF PARTICIPANTS** | **DESINGNATION** | **BANK/DEPARTMENT** | **CONTACT NO.** |
| 1 | SRI ATANU KUMAR | MD AND CEO | BANK OF INDIA | |
| 2 | SRI SWARUP DASGUPTA | EXECUTIVE DIRECTOR | BANK OF INDIA | |
| 3 | SRI SANJEEV SINHA | GENERAL MANAGER (oic) | RESERVE BANK OF INDIA | |
| 4 | SRI AJOY KUMAR SINGH | PRINCIPAL SECRETARY | DEPT. OF FINANCE, GOJ | |
| 5 | SRI ABOOBACKER SIDDIQUE | SECRETARY | DEPT. OF AGRICULTURE, GOJ | |
| 6 | SRI B K MISHRA | GENERAL MANAGER | SLBC JHARKHAND | |
| 7 | DR. GOPA KUMARAN NAIR | CHIEF GENERAL MANAGER | NABARD | |
| 8 | SRI GANESH TOPPO | DY. GENERAL MANAGER | SLBC JHARKHAND | |
| 9 | SRI SUBODH KUMAR | DY. GENERAL MANAGER | SLBC JHARKHAND | |
| 10 | SMT DEEPTHI JAYARAJ | SPECIAL SECRETARY | DEPT. OF FINANCE, GOJ | 9431133694 |
| 11 | SRI SANDEEP LAKRA | JOINT SECRETARY | | 9438917436 |
| 12 | SRI JANMEJOY MOHANTY | GENERAL MANAGER | STATE BANK OF INDIA | 8210998008 |
| 13 | SRI BINOD KUMAR PATTANAIK | GENERAL MANAGER | UNION BANK OF INDIA | 9903945720 |
| 14 | SRI DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA | DY. GENERAL MANAGER | PUNJAB NATIONAL BANK | 9431023304 |
| 15 | SRI AJAY KUMAR SINGH | DY. GENERAL MANAGER | CENTRAL BANK OF INDIA | 9264291876 |
| 16 | DR. H N DWIVEDI | DIRECTOR FISHERIES | GOVERNMENT OF JHARKHAND | 9835210462 |
| 17 | SRI SANJAY KUMAR | ASST. GENERAL MANAGER | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 8709316664 |
| 18 | SRI RUPESH KUMAR | ASST. GENERAL MANAGER | STATE BANK OF INDIA | 7992231918 |
| 19 | SRI N K SINGH | DY. GENERAL MANAGER | STATE BANK OF INDIA | 7600093435 |
| 20 | SRI ANAND KUMAR | DY. GENERAL MANAGER | UNION BANK OF INDIA | 9161174666 |
| 21 | SRI MANOJ KUMAR | ASST. GENERAL MANAGER | BANK OF BARODA | 7234842571 |
| 22 | SRI ARUN KUMAR | DY. GENERAL MANAGER | CANARA BANK | 7317714911 |
| 23 | SRI ANANT KUMAR | DY. ZONAL MANAGER | INDIAN BANK | 9960079564 |
| 24 | SRI HEMANT KUMAR TIWARI | DY. ZONAL HEAD | UCO BANK | 9476492047 |
| 25 | SRI SANJAY KUMAR KHEMKA | ZONAL MANAGER | BANK OF INDIA | 9640100700 |
| 26 | SRI SURENDRA SHARMA | ASST. DIRECTOR | MSME DI | 7860950389 |
| 27 | MS JYOTSNA GURIA | ASST. DIRECTOR | MSME DI | 8292028771 |
| 28 | DR. M SINHA | JOINT DIRECTOR | DIRECTORATE OF AGRICULTURE | 9430153640 |
| 29 | SRI ANIL KUMAR | STATE NODAL OFFICER | RSETI, JSLPS | 9431901016 |
| 30 | SRI AJAY KUMAR | DY. DIRECTOR CUM DY SECRETARY | PLANNING AND DEVELOPMENT DEPATMENT | 7766999725 |
| 31 | SRI R K SINGH | ASST. GENERAL MANAGER | SIDBI | 8769624381 |
| 32 | SMT PUNAM KINDO | SENIOR MANAGER | BANK OF BARODA | 8877115992 |
| 33 | SRI JAIDEV BISWAS | GENERAL MANAGER | JHARKHAND MILK FEDERATION | 7360035213 |
| 34 | SRI RAJESH KUMAR TIWARY | CEO | JSCB | 9431116305 |
| 35 | SRI MUKESH KUMAR | MANAGER | JSCB | 7766917111 |
| 36 | SRI RAMCHANDRA | DIVISIONAL MANAGER | CANARA BANK | 9430724980 |
| 37 | SRI MANIJ KUMAR GUPTA | REGIONAL HEAD | IDBI BANK | 7781021133 |
| 38 | SRI ONKAR NATH | MANAGER | UCO BANK | 7389623293 |
| 39 | SRI ABHAY KUMAR | CLUSTER HEAD | AXIS BANK | 7566142333 |
| 40 | SRI DHARMENDRA KUMAR | CLUSTER HEAD | HDFC BANK | 8335897070 |
| 41 | SRI SUBHASH KUMAR | STATE HEAD | AXIS BANK | 7260811600 |
| 42 | SRI RANJAM MISHRA | BRANCH HEAD | BANDHAN BANK | 9934315080 |
| 43 | SRI RAJ KUMAR KAMAL | RM - GBG | INDUSIND BANK | 7782948535 |
| 44 | SRI SYED SHABBIR AKHTER | REGIONAL HEAD | ICICI BANK | 9771499046 |
| 45 | SRI J K GUPTA | DIRECTOR | KVIC | 9004172285 |
| 46 | SRI NARENDRA KUMAR | LDM | GODDA | 7781000190 |
| 47 | SRI SUDHIR KUMAR | LDM | SAHEBGANJ | 9771438409 |
| 48 | SRIMANOJ KUMAR | LDM | PAKUR | 9546175303 |
| 49 | SRI SHANTI PRASAD TOPPO | LDM | LATEHAR | 7781011677 |

| S.N | NAME OF PARTICIPANTS | DESINGNATION | BANK/DEPARTMENT | CONTACT NO. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | SRI ANUKARAN TIRKEY | LDM | PALAMAU | 7463881957 |
| 51 | SRI SANJAY SRIVASTAVA | SBI | SBI | 7781011728 |
| 52 | SRI VIVEKANAND KUMAR | ASST. DIRECTOR | TELECOM, GOI | 9431701791 |
| 53 | SRI SANJAY KUMAR SAHU | | | 9955628857 |
| 54 | SRI SANJEEV KR CHOUDHARY | LDM | SIMDEGA | 7903780946 |
| 55 | SRI DEOBRAT SHARMA | LDM | CHATRA | 8002738027 |
| 56 | SRI SUDHAKAR PANDEY | LDM | HAZARIBAGH | 9407585820 |
| 57 | SRI MAHESH PRASAD | LDM | KODERMA | 8051071834 |
| 58 | SRI M D TIWARI | LDM | RAMGARH | 8709758808 |
| 59 | SRI SUNIL KUMAR | LDM | KHUNTI | 9931394765 |
| 60 | SRI NARENDRA KUMAR | LDM | GODDA | 7781000190 |
| 61 | SRI DIWAKAR SINHA | LDM | EAST SINGHBHUM | 8936802753 |
| 62 | SRI LAXMI NARAYAN LAGURI | LDM | WEST SINGHBHUM | 8210786477 |
| 63 | SRI BIRENDRA KR SHIT | LDM | SARAIKELA-KHARSAWAN | 9572024420 |
| 64 | SRI NAKUL SAHU | LDM | DHANBAD | 9431726018 |
| 65 | SRI S K NAG | LDM | LOHARDAGA | 9110054740 |
| 66 | SRI SREEKANT | LDM | RANCHI | 9798967181 |
| 67 | SRI KAMLESH SINHA | LDM | JAMTARA | 7889213363 |
| 68 | SRI RAVINDRA KR SINGH | LDM | GIRIDIH | 9102508171 |
| 69 | SRI RAJESH KR SINHA | LDM | BOKARO | 9835984831 |
| 70 | SRI JOHN HASDAK | OFFICER | GUMLA LDMO | 9431916498 |
| 71 | SRI SHATRUGAN LAL BAITHA | LDM | DEOGHAR | 9771435410 |
| 72 | SRI INDU BHUSHAN LALL | LDM | GARHWA | 9934363709 |
| 73 | SRI NAGENDRA KUMAR | NODAL OFFICER | KVIC | 9816728220 |
| 74 | SRI RAJEEV | ASST DIRECTOR | KVIC | 9431169393 |
| 75 | SRI RAJEEV RANJAN | SENIOR MANAGER | INDIAN BANK | 8617763005 |
| 76 | SRI HIMANSHU SHEKHAR | SENIOR MANAGER | BANK OF MAHARASTRA | 9905774643 |
| 77 | SRI SUDIPTO KR SINHA | CHIEF MANAGER | INDIAN OVERSEAS BANK | 9028147750 |
| 78 | SRI PRASHANT KUMAR | RDO | INDIAN OVERSEAS BANK | 7004759480 |
| 79 | SRI DHIRAJ | SPM | JSLPS | 8969170434 |
| 80 | SRI MANISH KUMAR | CHIEF MANAGER | PUNJAB AND SINDH BANK | 7292045636 |
| 81 | SRI MANISH MUDGAL | STATE HEAD | AIRTEL PAYMENTS BANK | 9815049544 |
| 82 | SRI BIKASH PADIA | CHIEF MANAGER | AIRTEL PAYMENTS BANK | 9932449258 |
| 83 | SRI CHANDAN ARORA | CLUSTER HEAD | UTKARSH SMALL FINANCE BANK | 8877954110 |
| 84 | SRI SANJEEV KR SINHA | MANAGER | FINO PAYMENT BANK | 9771459734 |
| 85 | SRI MANISH KR DWIVEDI | ZONAL HEAD | FINO PAYMENT BANK | 9934011010 |
| 86 | SRI AMIT KR JHA | CHIEF MANAGER | INDIA POST PAYMENT BANK | 9835043869 |
| 87 | SRI BADAL JHA | MANAGER | SOUTH INDIAN BANK | 9560410782 |
| 88 | SMT KIRAN MISHRA | CHIEF MANAGER | KOTAK MAHINDRA BANK | 9709000208 |
| 89 | SMT NEETU KUMARI | ASST. MANAGER | KARUR VYSYA BANK | 7091194716 |
| 90 | SRI TAHIR AZIZ | BRANCH MANAGER | JAMMU & KASHMIR BANK | 9906608262 |
| 91 | SRI NIRAK KUMAR | ASSISTANT BRANCH MANAGER | KARNATAKA BANK | 9771492660 |
| 92 | SRI ANAND KUMAR | CLUSTER HEAD | YES BANK | 7873962227 |
| 93 | SRI MANIKANT SINGH | CLUSTER HEAD | ESAF SMALL FINANCE BANK | 8294305207 |
| 94 | SRI ANUP KR PANDEY | REGIONAL MANAGER | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK | 9955114151 |
| 95 | SRI MALAY BOSE | REGIONAL HEAD | JANA SMALL FINANCE BANK | 9570093381 |
| 96 | SRI KUMAR SOURABH | MANAGER | IDFC FIRST BANK | 7574855780 |
| 97 | SRI PRASHANT PRADEEP | BRANCH MANAGER | FEDERAL BANK | 8927630100 |
| 98 | SRI AMRENDRA KUMAR | SM (P) | HUDCO RANCHI | 9431815999 |